

दिल्ली परिवहन विभाग लोगों में मोटर वाहन नियमों के पालन के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जगह चालान करवाने पर ज्यादा दबाव क्यों बनाती है?

अति विशेष सूचना

“परिवहन विशेष” हिन्दी दैनिक समाचार पत्र आर.एन.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त करने के बाद से आपके द्वारा प्राप्त भरपूर सहयोग से मार्च में अपने 2 साल पूरे कर चुका है। इन दो सालों में समाचार पत्र को निष्पक्ष रूप से चलाने में आप सभी का भरपूर सहयोग रहा है जिसके लिए प्रशासनिक विभाग परिवहन विशेष आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता है और आशा करता है की भविष्य में भी आपका सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। इन दो सालों में समाचार पत्र को राष्ट्रीय स्तर पर सभी शहरों और जिलों तक पहुंचाने और वहां की सही और सच्ची खबरें हम तक पहुंचाने वाले रिपोर्टरों का दिल से धन्यवाद।

आप सभी को यह जान कर खुशी होगी की “परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र” का द्वितीय वार्षिकी समारोह अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में सम्पन्न किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सड़कों को जाम और दुर्घटनाओं से मुक्त करवाने के साथ दिल्ली को प्रदूषण मुक्त राज्य का उद्देश्य रखा गया है। इस समारोह में निम्नलिखित मुद्दों पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा

1. लेन ड्राइविंग कितनी अनिवार्य?
2. “सड़क दुर्घटना से कैसे हो सकता है दबाव?”
3. “दिल्ली को कैसे प्रदूषण मुक्त राज्य बनाया जा सकता है?”

वाद-विवाद प्रतियोगिता में हिस्सेदारी लेने वाले वक्ताओं के वक्तव्य के साथ परामर्शदाताओं से चर्चा भी इस समारोह में रखी जा रही है। इसके साथ इस आयोजन में भारत देश में निर्मित ई वाहनो, वीएलटीडी संयंत्र, एवम् अन्य उपयोगी स्टाल भी सब को आकृषित करने के लिए उपलब्ध होंगे। इस समारोह में

1. सबसे अच्छा विचार / तर्क और समाधान प्रदान करने वाले वक्ता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
2. परिवहन क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले संगठनों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
3. सड़क सुरक्षा के प्रति कार्य करने वाले संगठनों के पदाधिकारियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
4. परिवहन विशेषों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
5. समाचार पत्र से अलग अलग राज्यों से जुड़े एंकर, वीडियो ग्राफर, रिपोर्टर, लेखक, ज्योताचार्य, कवि एवम् सहायकों को सम्मानित किया जाएगा।

संजय कुमार बाटला
संपादक

संजय बाटला

दिल्ली भारत देश की राजधानी पर सड़कों के नाम पर

1. अधिक्रमिit सड़के,
2. टूटी फूटी गड्ढों के साथ गंदगी से भरपूर सड़के,
3. ना सड़कों पर पैदल पथ,
4. ना ही पैदल यात्रियों के लिए सड़कों को पार करने के लिए अंडर/ओवर ब्रिज,
5. अतिक्रमण के साथ बिना नियम कायदे के सड़कों पर चल रहे कंस्ट्रक्शन कार्य,

कैसे दिल्ली की सड़कों पर समय से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मोटर वाहन चालक को नियमों का पालन।

1. सार्वजनिक सवारी सेवा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें पर सेवा शून्य कैसे कोई सार्वजनिक सवारी सेवा पर भरोसा करे ?
2. दिल्ली में सार्वजनिक सवारी सेवा को सुखद एवम् समयानुसार सभी क्षेत्रों में प्रदान करने वाली दिल्ली परिवहन निगम के पास अपने नाम से पंजीकृत एक भी बस नहीं पर विज्ञापनों के अनुसार दावा 10000 पार,
3. घर से मुख्य सड़क तक और सड़क से गंतव्य स्थान तक जनता के पहुंचने के लिए एक भी सुरक्षित सार्वजनिक सवारी वाहन सेवा उपलब्ध



नहीं,

दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त, दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए कोई जागरूकता अभियान नहीं

दिल्ली की जनता निजी वाहनों की जगह किस सार्वजनिक सवारी सेवा के भरोसे पहुंचे समयानुसार सुरक्षित और सुखद अनुभव से गंतव्य

स्थान पर बताने के लिए कोई नहीं।

क्या दिल्ली की जनता और बाहरी राज्यों/बाहरी देशों से दिल्ली में आए हुए नागरिक

1. अनाधिकृत सवारी वाहन सेवा,
2. बिना चालक प्रमाण पत्र (चालक लाइसेंस) के चलाने वाली,
3. बिना फिटनेस, बिना इंश्योरेंस, बिना पूर्ण

वाहन के कागजों के सड़कों पर चल रहे वाहनों

4. ऐसे वाहनो जिनके मालिकों का परिवहन विभाग के पास डाटा ही उपलब्ध नहीं के भरोसे ऊपरलिखित श्रेणी के सवारी सेवा वाहनो द्वारा दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षित, सुखद यात्रा करे और परिवहन विभाग इस बात की गारंटी देगा की ऐसे वाहनो से गंतव्य स्थान तक जनता सुगम सुरक्षित पहुंच जाएगी।

परिवहन विभाग को इन वाहनो के सड़कों पर बखौफ चलने से कोई परेशानी नहीं आरिख क्यों ?

* परिवहन विभाग को राजस्व में इजाफा करवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने से, सुरक्षित सार्वजनिक सवारी सेवा उपलब्ध कराने से परेशानी है।

* अधिकृत रूप से चल रहे सार्वजनिक सवारी सेवा के वाहनो द्वारा की गई छोटी गलती पर चालान कर मोटा जुर्माना वसूल करवाने से मतलब है।

अब आप ही बताए जनता के हित के लिए बनाए गए विभाग और उसमें जनहित के प्रति ध्यान रखने के लिए नियुक्त आई.ए.एस. अधिकारी ही जनता के हित की जगह राजस्व के लिए जनता का अहित करने लगे तो कैसे मिलेगा दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षित सुखद यात्रा, बड़ा सवाल ?

दिल्ली में अब शुरू होगा प्लास्टिक वाली सड़कों का चलन सड़कों की उम्र बढ़ाने और कचरे के निपटान के लिए सीआरआरआई से मदद ले रही सरकार

आज से दिल्ली के 70 से ज्यादा रूटों पर दौड़ेंगी 320 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें

राजधानी दिल्ली में अब प्लास्टिक वाली सड़कों का दौर शुरू होने वाला है। सरकार सड़कों की उम्र बढ़ाने और कचरे के निपटान के लिए सीआरआरआई से मदद ले रही है। प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़कें दो साल तक अधिक चलेंगी। दिल्ली कैट में पहले किए गए प्रयोग सफल रहे हैं। इस तकनीक से सड़कों की दशा में सुधार होगा।

नई दिल्ली। सड़कें बनाए जाने के बाद ज्यादा दिनों तक चलें, इसे देखते हुए दिल्ली में प्लास्टिक वाली सड़कों का दौर शुरू होने वाला है, इससे दिल्ली में सड़कों की उम्र दो साल और बढ़ सकेगी। ऐसे में दिल्ली में सड़कों के जल्द टूट जाने की समस्या से निजात मिल जाने की संभावना है। दिल्ली में प्लास्टिक मिक्स सामग्री की सड़क बनाने के लिए दिल्ली सरकार सीआरआरआई (केंद्रीय सड़क अनुसंधान संगठन) से मदद लेने पर विचार कर रही है।

सीआरआरआई भी मदद देने को तैयार है, जल्द ही दोनों के बीच बैठक होने की संभावना है। कुछ साल पहले सीआरआरआई ने प्रयोग के तौर पर दिल्ली कैट में इस तरीके की सड़क का किया निर्माण किया था, जिसके परिणाम बेहतर आए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से सड़कों की उम्र कम से कम दो साल और बढ़ जाएगी। एक किलोमीटर सड़क बनाने में एक टन तक प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जा सकता



है। इससे प्लास्टिक कचरे का भी निपटान हो सकेगा।

सड़क के क्षेत्र में दिल्ली में एक बड़ा प्रयोग होने की संभावना

दिल्ली में भाजपा की सरकार आने के बाद से प्रशासनिक स्तर पर तमाम तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। बदलाव कामकाज के तौर तरीके तरीकों और नई-नई तकनीक के प्रयोग करने के भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अगर सड़कों की बात करें तो इस क्षेत्र में दिल्ली में एक बड़ा प्रयोग होने की संभावना है।

दिल्ली सरकार सड़कों की दशा को लेकर चिंतित है जो पिछले 10 साल में अक्सर खराब ही रही हैं। इस समस्या से जनता को सबसे ज्यादा जूझना पड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार अब सड़कों की मजबूती और लंबे समय तक चलने वाली सड़क बनाने की रणनीति के तहत प्लास्टिक वाली सड़कों पर विचार कर रही है।

कैसे तैयार होता है प्लास्टिक का कचरा

सीआरआरआई के वैज्ञानिकों के अनुसार सड़क बनाने की कोलतार व रोड़ी मिक्स सामग्री में प्लास्टिक के उस कचरे को शामिल किया जाता है जो बेकार हो चुकी प्लास्टिक की वस्तुओं को मशीनों द्वारा काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार किया जाता है। मानक के अनुसार 1 किलोमीटर सड़क बनाने में लगभग एक टन तक ऐसा कचरा उपयोग किया जा सकता है।

इसका क्या होता है लाभ

वैज्ञानिकों की मानें तो मिक्स सामग्री में प्लास्टिक के कचरे के डाले जाने से सड़क में मजबूती आती है और सड़क जल्द खराब होने से बचती है। इस तरह की सड़कें बरसात के समय भी जल्द खराब नहीं होती हैं। सड़कों की उम्र दो साल तक बढ़ाई जा सकती है यानी जो सड़क पांच साल तक चलती है उसे सात साल

तक बचाया जा सकता है। मिक्स सामग्री में प्लास्टिक कचरा डालने से बहुत मामली खर्च बढ़ता है।

सफल रहा है इसका प्रयोग प्लास्टिक कचरा मिक्स सड़कें बनाने का प्रयोग कुछ साल पहले दिल्ली में कैट एरिया में किया गया था। जहां सदर बाजार रोड को बनाया गया था, जो आज तक अच्छी हालत में है। इससे पहले भी कुछ स्थानों पर इसका प्रयोग किया गया था, जो सफल रहा है।

सड़कों को लेकर अभी क्या है स्थिति दिल्ली में लोक निर्माण विभाग के पास 1259 किलोमीटर सड़कें हैं। ये सड़कें प्रमुख सड़कें हैं जिन पर शहर का अधिक दबाव रहता है। पीडब्ल्यूडी की मानें तो सड़क पांच साल तक चलने में ही खराब हो जाती है, इस दौरान कई बार मरम्मत भी करानी पड़ती है। अधिकारियों के अनुसार सड़क पर भरने वाले पानी के कारण भी जल्दी सड़कें खराब होती हैं।

क्या कहते हैं सीआरआरआई के वैज्ञानिक

हम दिल्ली सरकार से इस बारे में बात कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी मुख्यमंत्री के साथ इस बारे में बैठक होने की संभावना है। भाजपा सरकार सड़कों को लेकर बेहतर काम करने के प्रयास में है। अगर इस तकनीक को अपनाया जाता है, शहर की जनता को बहुत लाभ मिल सकेगा।

- डॉ. अशिका बहल, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, सीआरआरआई

दिल्ली सरकार 22 अप्रैल को 320 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारने की तैयारी में है। इनमें 240 मिनी और 80 स्टैंडर्ड साइज की बसें शामिल हैं। मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री की मौजूदगी में कुशक नाला डिपो से इन्हें रवाना किया जाएगा। ये बसें 70 से ज्यादा रूटों पर चलेंगी जिनमें पूर्वी और मध्य दिल्ली के रूट प्रमुख हैं।



परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राजधानी में बसों की कमी से जूझ रही दिल्ली की जनता को आने वाले दिनों में कुछ राहत मिल सकती है। दिल्ली सरकार 22 अप्रैल को सड़कों पर 320 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें उतारने की योजना बना रही है। जिससे लोगों का आवागमन आसान होगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री डा. पंकज कुमार सिंह की मौजूदगी में कुशक नाला डिपो से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की योजना है।

बसों को 70 से अधिक रूटों पर लगाया जाएगा

जो बसें उतारने की बात हो रही है, उनमें नौ मीटर लंबी 240 मिनी इलेक्ट्रिक बसें के अलावा 12 मीटर

लंबी स्टैंडर्ड साइज वाली 80 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इन बसों को 70 से अधिक रूटों पर लगाया जाएगा। जिसमें सबसे ज्यादा पूर्वी व मध्य दिल्ली के रूट शामिल हैं।

इसी के साथ नौ मीटर लंबी मोहल्ला बसों की नए नाम दिल्ली इलेक्ट्रिक क्वीक इंटरचेंज (देवी) के साथ आधिकारिक शुरुआत भी हो जाएगी।

दिल्ली में निर्माण कार्य से जुड़े रिश्वत कांड के बाद, पुलिस कमिश्नर सख्त, पुलिस वालों को दी हिदायत

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली में निर्माण कार्य करने की अनुमति को लेकर बीते दिनों दिल्ली पुलिस के एएसआई ने जिस तरह दो लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है, एक बार फिर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ खड़े हुए थे. अब एक बार फिर पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने आदेश जारी कर सभी को हिदायत दी है कि पुलिस कर्मी इसके लिए अधिकृत नहीं हैं.

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद एक बार फिर से सूचित किया गया है कि अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन को रोकना या ध्वस्त करना संबंधित सिविक विभागों, जैसे कि डीडीए, एमसीडी, रेवेन्यू विभाग का ही मूल एवं प्राथमिक कर्तव्य है. कोई भी पुलिस अधिकारी व कर्मी, खुद से ही, इस तरह के कार्यों को रोकने हेतु अधिकृत नहीं हैं.

संजय अरोड़ा ने कहा है कि पुलिस का कर्तव्य मात्र ऐसी गतिविधियों की

सूचना सम्बंधित विभाग को देने भर की है. पुलिस विभाग से अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन को रोकने, या ध्वस्त करने करने के लिए जब भी सिविक विभाग के कर्मचारी मौके पर आते हैं, तब एसी सूरत में, उनके द्वारा सहायता मांगने पर, उचित सहायता और सुरक्षा प्रदान करना पुलिस का काम है.

पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल: पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों व थानाध्यक्ष से इस बारे में निर्देश देने और जागरूकता पैदा करने को कहा है. दरअसल, उक्त रिश्वतकांड के बाद इस संबंध में 16 अप्रैल को दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिख पुलिस कर्मियों को आदेश देने को कहा था. इससे पहले भी दिल्ली में निर्माण कार्य से संबंधित वैध/अवैध मामले को लेकर पुलिस की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही है, इस पर रोक के लिए कई आदेश पुलिस महकमे और सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन इसमें पुलिस की भूमिका पर हमेशा से

सवाल उठते रहे हैं.

दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार की सख्त हिदायतों के बावजूद दिल्ली पुलिस में कथित तौर पर निर्माण क्षेत्र में थाना स्तर पर रिश्वत का नहीं खेल नहीं थमा. जिस पर दिल्ली में निर्माण कार्य से जुड़े मामलों में पुलिस की दखलजांदगी पर गृह मंत्रालय ने गत दिनों में आपत्ति भी जताई थी. जिसके बाद दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद शहरी विकास विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी कर पुलिस को दूर रहने का दिया आदेश था.

बावजूद दिल्ली पुलिस का एएसआई जिस तरह दो लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ था. दिल्ली में निर्माण कार्य की अनुमति जारी करने में पुलिस की भूमिका स्पष्ट करने के लिए दिल्ली में बनी बीजेपी सरकार ने एक मार्च को एक सर्कुलर जारी किया था जो गृह मंत्रालय के आदेश पर जारी किया गया था. अब दोबारा पुलिस कमिश्नर ने महकमे के लिए उक्त आदेश जारी किया है।

कार्यालय आयुक्त पुलिस: दिल्ली
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001

परिपत्र

संख्या: 25/2025

विषय :- अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन में पुलिस कि भूमिका व दायित्व

दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश (संख्या) के द्वारा, एक बार फिर से सूचित किया गया है कि अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन को रोकना या ध्वस्त करना, सम्बंधित सिविक विभागों, जैसे कि DDA/CMCD/Revenue इत्यादि का ही मूल एवं प्राथमिक कर्तव्य है। कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मी, खुद से ही, इस तरह के कार्यों को रोकने हेतु अधिकृत नहीं है। पुलिस का कर्तव्य मात्र ऐसी गतिविधियों कि सूचना सम्बंधित विभाग को देने भर की है।

पुलिस विभाग से अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन को रोकने, या ध्वस्त करने हेतु, जब भी सिविक विभाग के कर्मचारी मौके पर आते हैं, तब एसी सूरत में, उनके द्वारा सहायता मांगने पर, उचित सहायता व सुरक्षा प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य बना रहेगा।

सभी अधिकारी व थानाध्यक्ष इस निर्देश के बारे में उचित जागरूकता पैदा करें व इस पर अमल करवाएं।

यह परिपत्र, अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन सम्बंधित पूर्व में जारी सभी परिपत्रों/स्थायी आदेशों की निरंतरता में जारी किया जाता है।

(संजय अरोड़ा)
आयुक्त पुलिस, दिल्ली।

क्रमांक 3951-4100 /अभिलेख शाखा/पुं मुं, दिल्ली दिनांक 19/04/2025

टॉलवा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathiasanjaybathia@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

मारुति सुजुकी विटारा का सीएनजी वर्जन हुआ बंद, अब सिर्फ पेट्रोल और हाइब्रिड के साथ आएगी एसयूवी

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रैंड विटारा सीएनजी बंद देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट और तकनीक के साथ कारों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली Grand Vitara के CNG वर्जन को बंद कर दिया गया है। अब एसयूवी को किस तरह के इंजन विकल्प में ऑफर किया जाएगा। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत को प्रमुख वाहन निर्माता Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से हाल में ही अपनी कारों के दाम बढ़ाए गए थे। जिसके साथ ही कई मॉडल को अपडेट भी किया गया था। इसी क्रम में मारुति की मिड साइज एसयूवी Grand Vitara के सीएनजी वेरिएंट्स

को हटा (Grand Vitara CNG Discontinued) दिया गया है। अब किस तरह के इंजन विकल्प के साथ एसयूवी को ऑफर किया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Grand Vitara के CNG वेरिएंट्स हुए बंद

मारुति सुजुकी की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर ग्रैंड विटारा को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से हाल में ही एसयूवी को अपडेट किया गया था। 8 अप्रैल 2025 को एसयूवी की कीमत में 41 हजार रुपये तक बढ़ाए गए थे। जिसके साथ ही एसयूवी के कुछ वेरिएंट्स को बंद कर दिया गया है। इसमें CNG के सभी वेरिएंट शामिल हैं। बंद करने से पहले एसयूवी के डेल्टा और जेटा वेरिएंट्स में सीएनजी को ऑफर किया जाता था।

मिलती थी 26.60 को माइलेज
Maruti Grand Vitara के सीएनजी वर्जन में भी

1.5 लीटर का इंजन दिया जाता था। जिससे एसयूवी को 88 पीएस की पावर और 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। इस इंजन के साथ एसयूवी को एक किलोग्राम सीएनजी में 26.60 किलोमीटर तक चलाया जा सकता था।

यथा है कारण

मारुति की ओर से ग्रैंड विटारा के सीएनजी वेरिएंट्स को बंद करने की औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह संभावना जताई जा रही है कि कम मांग के कारण मारुति की ओर से सीएनजी वेरिएंट्स को हटा दिया गया है।

पेट्रोल और हाइब्रिड तकनीक के साथ मिलेगी एसयूवी

मारुति ग्रैंड विटारा एसयूवी को अब सिर्फ पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक (Grand Vitara petrol and hybrid variants) के साथ ही ऑफर किया जा रहा है। इस एसयूवी में 1.5 लीटर का ही पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग

हाइब्रिड इंजन दिया जाता है। जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प ऑफर किए जाते हैं।

कितनी है कीमत

मारुति ग्रैंड विटारा में नए फीचर्स जोड़ने के बाद अब इसकी कीमत को भी अपडेट किया गया है। एसयूवी को 11.42 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 20.68 लाख रुपये रखी गई है। एसयूवी के अब कुल 18 वेरिएंट्स को ऑफर किया जा रहा है।

किनसे है मुकाबला

मारुति की ओर से ग्रैंड विटारा एसयूवी को चार मीटर से ज्यादा बड़ी एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Toyota Urban Cruiser Hyryder, Honda Elevate, Hyundai Creta, Kia Seltos, MG Astor जैसी एसयूवी के साथ होता है।



एमजी विंडसर ईवी के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की अग्रिम भुगतान के बाद जाएगी कितनी ईएमआई

परिवहन विशेष न्यूज

कार फाइनेंस प्लान JSW MG की ओर से EV सेगमेंट में MG Windsor EV को ऑफर किया जाता है। इसके बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर EV सेगमेंट की गाड़ी को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। ब्रिटिश वाहन निर्माता JSW MG मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली MG Windsor EV को काफी पसंद किया जाता है। अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

MG Windsor EV Price

एमजी मोटर्स की ओर से Windsor EV के बेस वेरिएंट को 13.99 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 14.93 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 13.99 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के अलावा करीब 6200 रुपये आरटीओ और इश्योरेंस के करीब 74 हजार रुपये देना होगा। इसके अलावा इसके लिए टीसीएस चार्ज के 13998 रुपये देना होगा। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 14.93 लाख रुपये हो जाती है।

दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI



अगर इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद आपको करीब 12.93 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 12.93 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 20814 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात

साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी कार

अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 12.93 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 20814 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप MG Windsor EV के लिए करीब 4.54 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत

एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 19.48 लाख रुपये देंगे।

किनसे होगा मुकाबला

JSW MG की ओर से Windsor EV को इलेक्ट्रिक गाड़ी के तौर पर लाया जाता है। बाजार में इसे कई एसयूवी से चुनौती मिलती है, लेकिन इसका सीधा मुकाबला Tata Curvv EV, Mahindra BE6 जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ होता है।

बार-बार नहीं देना होगा टोल टैक्स, एक ही बार में सालभर की हो जाएगी छुट्टी, फास्टैग पर नितिन गडकरी ला रहे नई पॉलिसी



परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश में हजारों लोग रोजाना नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे पर सफर करते हैं। इन पर सफर करने के लिए Toll Tax भी वसूल किया जाता है। बार बार टोल देने के कारण कई बार लोग परेशान भी हो जाते हैं। अब इसका समाधान केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। किस तरह से लोगों को राहत देने की बात कही जा रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

जल्द लागू होगी नई टोल नीति

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से देशभर में जल्द ही नई टोल नीति को लागू किया जा सकता है। जिससे टोल से संबंधित परेशानियों का समाधान हो सकता है। हालांकि अभी इस बारे में किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

कैसे होगा समाधान

जानकारी के मुताबिक नई नीति में सरकार की ओर से लोगों को यह सुविधा दी जाएगी कि वह अपने Fastag को तीन हजार रुपये में रिचार्ज करवा सकते हैं, जिसके बाद अगले एक साल तक उनको किसी भी टोल प्लाजा पर टैक्स

नहीं देना होगा। इस रिचार्ज के बाद वह असिमित संख्या में टोल प्लाजा पार कर सकते हैं। जिससे बार बार टोल प्लाजा पर टैक्स देने और मिनिमम बिलेस रखने की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है।

एक और विकल्प पर किया गया था विचार

रिपोर्ट्स के मुताबिक केन्द्र सरकार की ओर से एक और विकल्प पर भी विचार किया गया था। जिसके मुताबिक नई कार

खरीदने पर ही 30 हजार रुपये दिए जाएं तो अगले 15 सालों तक किसी भी टोल प्लाजा पर पेमेंट नहीं देनी होगी। लेकिन लाइफटाइम पास पर सभी पक्षों में सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण इस विकल्प को छोड़ दिया गया।

किससे मिलेगा फायदा

सरकार की ओर से नई नीति के तहत तीन हजार रुपये के फॉर्मूले को लागू किया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा ऐसे लोगों को होगा जो हर महीने एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे का उपयोग करते हैं।

कैसे होगी नुकसान की भरपाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की ओर से इस तरह के फैसले को लागू किया जाता है तो इसका नुकसान कैम्पेनरों और कॉन्ट्रैक्टर्स को होगा। जिसकी भरपाई सरकार की ओर से एक खास फॉर्मूले के तहत की जाएगी। फॉर्मूले के तहत टोल प्लाजा से निकलने वाले वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा और कंसेन्सर और कॉन्ट्रैक्टर्स के दावे और वास्तविक वसूली में जो अंतर मिलेगा उसकी भरपाई एक खास फॉर्मूले के साथ की जाएगी।

वोक्सवैगन टिगुआन आर लाइन हुई भारत में लॉन्च, फॉर्च्यूनर, ग्लोस्टर को मिलेगी चुनौती, कीमत 48.99 लाख रुपये से शुरू

परिवहन विशेष न्यूज

टिगुआन आर लाइन एसयूवी भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को सबसे ज्यादा किया जाता है। जर्मनी की वाहन निर्माता Volkswagen की ओर से औपचारिक तौर पर देश में फुल साइज एसयूवी के तौर पर Tiguan R Line SUV को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें किस तरह के फीचर्स मिलेंगे। कितना दमदार इंजन मिलेगा। किस कीमत पर इसे लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। जर्मनी की वाहन निर्माता

Volkswagen की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से 14 April 2025 को औपचारिक तौर पर Volkswagen Tiguan R-Line को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर एसयूवी को खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्च हुई Volkswagen Tiguan R-Line

फॉक्सवैगन की ओर से भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर Tiguan R-Line को लॉन्च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इसे फुल साइज एसयूवी सेगमेंट

में लॉन्च किया गया है।

कितना दमदार इंजन

फॉक्सवैगन की ओर से टिगुआन आर-लाइन एसयूवी में दो लीटर की क्षमता का टोएसआई ईवो पेट्रोल इंजन दिया गया है। जिससे 204 पीएस की पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इसमें 7स्पीड डीएसजी ट्रांसमिशन को दिया गया है। इसके साथ ही इसमें 4मोशन ऑल व्हील ड्राइव क्षमता को दिया गया है, जिससे इसे किसी भी तरह की सड़क पर चलाया जा सकता है।

कैसे हैं फीचर्स

Volkswagen Tiguan R Line में निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। जिसमें 15 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, 10.25 इंच डिजिटल इस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आईडीए वॉयस असिस्टेंट, रोटर कंट्रोलर के साथ स्क्रीन, आठ स्पीकर ऑडियो सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल, दो वायरलेस चार्जिंग पॉड, एंबिएंट लाइट, पैनोरमिक सनरूफ, मैट्रिक्स हेडलाइट, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, एलईडी डीआरएल, रूफ रैल जैसे फीचर्स को भी दिया गया है।

कैसे हैं सेफ्टी फीचर्स

एसयूवी में सुरक्षा का भी पूरा ध्यान



रखा गया है। इसमें नौ एयरबैग, टीपीएमएस, हिल स्टार्ट असिस्ट और हिल डीसेंट कंट्रोल, फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक, 21 फीचर्स के साथ Level 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स को दिया गया है।

कितनी है कीमत

फॉक्सवैगन की ओर से एसयूवी को 48.99 लाख रुपये की इंट्रोडक्टी कीमत पर लॉन्च किया गया है। कुछ समय बाद

इसकी कीमतों में बदलाव भी किया जा सकता है।

किनसे है मुकाबला

Volkswagen Tiguan R-Line एसयूवी को फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Toyota Fortuner, Legend, JSW MG Gloster और जल्द लॉन्च होने वाली Skoda Kodiaq से होगा।

फैमिली के साथ जाने के लिए बेस्ट हैं ये सात सीटों वाली MPV, कीमत 6.09 लाख रुपये से शुरू

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में सर्वश्रेष्ठ एमपीवी अब सर लोग अपने परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा करना पसंद करते हैं। छोटी कार में पांच से ज्यादा लोगों के साथ सफर करने में परेशानी होती है। आप भी इस तरह अपने परिवार के साथ सफर करते हैं तो सात सीटों वाली MPV को किस कंपनी की ओर से ऑफर किया जाता है। किन विकल्पों पर आप विचार कर सकते हैं। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में सड़कों की स्थिति में पिछले कुछ सालों में काफी सुधार हुआ है। जिस कारण लोग अब कार से भी लंबी दूरी की यात्रा करना पसंद करते हैं। कई लोग अपने बड़े परिवार के साथ भी कार से सफर करते हैं। रिपोर्ट्स के

अगर आप भी पांच से ज्यादा लोगों के साथ सफर करना चाहते हैं तो किस निर्माता की ओर से कौन सी सात सीटों वाली एमपीवी (7 Seater MPVs in India) को ऑफर किया जाता है। किस कीमत पर इनको खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Renault Triber MPV

भारतीय बाजार में सबसे सस्ती एमपीवी के तौर पर रेनो की ओर से ट्राइबर की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस गाड़ी में एक लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया जाता है। जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। रेनो ट्राइबर एमपीवी की एक्स शोरूम कीमत 6.09 लाख रुपये से शुरू हो जाती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 8.97 लाख रुपये तक है। रिपोर्ट्स के

मुताबिक रेनो की ओर से जल्द ही इसके फेसलिफ्ट वर्जन को बाजार में पेश किया जा सकता है।

Maruti Ertiga है पसंदीदा एमपीवी

मारुति सुजुकी की ओर से एमपीवी सेगमेंट में अर्टिगा की बिक्री की जाती है। इस गाड़ी को भी 1.5 लीटर पेट्रोल और सीएनजी इंजन के विकल्प के साथ ऑफर किया जाता है। मारुति की यह गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा शोरूम कीमत 8.96 लाख रुपये से शुरू होती है। इसमें कई बेहतरीन फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स कीमत 13.25 लाख रुपये है।

Kia Carens को भी किया जाता है पसंद

पेट्रोल के साथ ही डीजल इंजन को पसंद करने वालों को Kia की ओर से Carens

एमपीवी का विकल्प दिया जाता है। इस गाड़ी में 1.5 लीटर की क्षमता के पेट्रोल और डीजल इंजन दिए जाते हैं। इसमें नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ ही टॉर्क इंजन के विकल्प भी मिलते हैं। एमपीवी की एक्स शोरूम कीमत 10.59 लाख रुपये से लेकर 19.49 लाख रुपये के बीच है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ महीनों के दौरान एमपीवी के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया जा सकता है।

Toyota Rumion की भी है मांग

मारुति अर्टिगा की तरह ही डिजाइन वाली टोयोटा की एमपीवी Rumion को भी बाजार में ऑफर किया जाता है। इसमें भी 1.5 लीटर की क्षमता का नेचुरल एस्पिरेटेड और सीएनजी इंजन का विकल्प मिलता है। एमपीवी की एक्स शोरूम कीमत 10.54 लाख रुपये से लेकर 13.83 लाख रुपये के बीच है।



फैमिली के लिए बेस्ट हैं ये 7 सीटर MPVs

ओडिशा में जाति आधारित जनगणना और पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकार, सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन का आह्वान



मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर: ओडिशा की राजनीतिक स्थिति और दोगली सरकार की विफलता ने राज्य के लोगों को अभिभूत कर दिया है। इस संदर्भ में, समाजवादी पार्टी ओडिशा, राज्य समिति ने ओडिशा के पिछड़े, हाशिए पर और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के लिए अपना रुख स्पष्ट किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के 17 तारीख के ओडिशा दौरे के बाद ओडिशा के पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सामाजिक न्याय का द्वार खुल गया है और राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। कई वर्षों तक पार्टी के ओडिशा अध्यक्ष रहे पूर्व अध्यक्ष की पार्टी विरोधी गतिविधियों और लालची रवैये के कारण पार्टी का संगठन कमजोर हो गया था। इसका पता चलने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्होंने फंड हड़पने के आरोप में नोटिस भी दिया गया है

और कानूनी कार्रवाई चल रही है। तथा नये अध्यक्ष शिव हाथी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ओडिशा में अपने संगठन को मजबूत करेगी, यह बात राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने ओडिशा दौरे के दौरान स्पष्ट कर दी है। इसलिए पार्टी अध्यक्ष बदलने के बारे में मीडिया में प्रसारित की जा रही खबरें पूरी तरह से निराधार और झूठी हैं। ओडिशा की जनता जानती है कि लंबे समय तक कांग्रेस और बीजद ओडिशा में सत्ता में रही और तथाकथित नेताओं ने कभी भी ओबीसी के हितों की बात नहीं की। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों ने केन्द्रीय व राज्य मंत्रों रहते हुए पिछड़े वर्गों के हितों की अनदेखी की और अपने हितों को साधा, वे अब सत्ता से बाहर होने के बाद खुद को पिछड़े वर्गों का हितैषी बता रहे हैं।

समाजवादी पार्टी डी.ए.: राम मनोहर लोहिया, अम्बेडकर और मुलायम सिंह यादव के आदर्शों पर भी एक अनुशासित पार्टी, जो पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों के संघर्ष से उभरी है।

ओडिशा के वर्तमान राजनीतिक माहौल में कुछ नेताओं द्वारा खुद को पिछड़े वर्गों का हिमायती बताकर राज्य की जनता को गुमराह करने के प्रयास निरर्थक हैं। साथ ही, यदि किसी अन्य राजनीतिक दल का नेता समाजवादी पार्टी का समर्थक बनना चाहता है तो समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करेगी। ओडिशा में जाति आधारित जनगणना और सामाजिक न्याय के लिए समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर से अपनी सांगठनिक स्थिति को मजबूत करेगी और आगामी 2027 के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव हाथी यादव के नेतृत्व में पूरे ओडिशा से अपने उम्मीदवार उतारेगी। ओडिशा की डबल इंजन सरकार ने पिछले 11 महीनों में ओडिशा के खनन, जल और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विभिन्न निजी कंपनियों को हस्तांतरित करके ओडिशा की अर्थव्यवस्था को लूट लिया है। समाजवादी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। इसी प्रकार, समाजवादी पार्टी राज्य समिति मांग करती है कि मंडल आयोग की

रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा में पिछड़े वर्गों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए। ओडिशा पर कई वर्षों तक उच्च वर्गों का शासन रहा है। जिन्होंने कभी भी पिछड़े वर्गों के हितों के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अब अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए पिछड़े वर्गों के हितों की लड़ाई का आह्वान करना उनके लिए एक साजिश और मजाक है। समाजवादी पार्टी ओडिशा राज्य समिति, ओडिशा के शिव हाथी के नेतृत्व में, 54% ओबीसी या पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। इसके साथ ही जाति जनगणना को कानूनी प्रक्रिया में बदलने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल लोगों की भागीदारी होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ओडिशा दौरे के बाद प. समाजवादी पार्टी का दृढ़ निश्चय है कि डीए समीकरण की राजनीति में नया मानक स्थापित करेगी।

प्रधानमंत्री के हाथों पी एम पुरस्कार से नवाजे गये रविशंकर शुक्ला

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

सरायकेला। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए उन्नत पाया गया है। इसी बाबत नीति आयोग की प्रधानमंत्री पुरस्कार सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने आज दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ग्रहण किया।

आज सिविल सेवा दिवस समारोह में पीएम पुरस्कार, 2024 की आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम श्रेणी के तहत 5 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों को सम्मानित किया गया। नीति आयोग की यह पुरस्कार विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के ईमानदार, व्यवहार कुशल आई एएस रवि शंकर शुक्ला को दी है।

सनद रहे कि आजादी के बाद घोर उपेक्षित सरायकेला का एक ब्लॉक गम्हरिया हेतु यह पारितोषिक मिला है। जिसने देश भर के 500 आकांक्षात्मक ब्लॉकों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास जैसे पांच फोकस क्षेत्रों में बेहतर शासन, सेवा वितरण और प्रमुख संकेतकों की निगरानी के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने हेतु दी गयी है।



ममता को बर्खास्त कर बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर धरना प्रदर्शन

विश्व हिन्दू परिषद ने राष्ट्रपति के नाम सरायकेला उपायुक्त को दिया ज्ञापन

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

सरायकेला, सरायकेला खरसावां जिला में वक्फ बिल संशोधन की आड़ में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा पर विशेष प्रदर्शन करते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कराने हेतु सैकड़ों की तादाद में लोगों ने उपायुक्त कार्यालय में पहुंच कर बेनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। कभी कांग्रेस फिर भाजपा फिर झामुमो- भाजपा नेतृत्वकर्ताओं का राजनीतिक गढ़ रहा सरायकेला में अब यह प्रदर्शन काफी समय बाद विश्व हिन्दू परिषद एवं सहयोगी इकाई के सदस्यों की तरफ से जिलाध्यक्ष जेएन दास के नेतृत्व में शनिवार को जिला मुख्यालय में हिन्दू हित में देखा गया।

प्रदर्शन के पश्चात भारत के राष्ट्रपति के नाम सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रविशंकर



शुक्ला को एक ज्ञापन भी गया सौंपा गया। उक्त ज्ञापन में विश्व हिन्दू परिषद ने राष्ट्रपति से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाला है। हिंसा फैलने का कारण दर्शाते हुए निराकरण राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही गयी है। यहां धरना-प्रदर्शन के दौरान बंगाल हिंसा पर आक्रोश व्यक्त करते नारे भी लगाये गये।

प्रदर्शन कारियों में भाजपा नेता रमेश हांसदा, बजरंग दल के नगर संयोजक राज रंजन दे, विश्व हिन्दू परिषद के जिला उपाध्यक्ष अजय मिश्रा, खरसावां प्रखंड अध्यक्ष सुब्रत सिंहदेव, बजरंग जिला मंत्री उमाकांत महतो, जिला संयोजक अरुण गोराल, कोषाध्यक्ष संजय चौधरी, सरायकेला नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मिनाक्षी पट्टनायक, पिकी मोदक, रितिका मुखी, लक्ष्मण सिंह, आदित्यपुर से संघ के अनेकों अनुपंगी

धर्मगुरु दीवान साहब के बधावा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब

जगदीश सीरवी

बिलाड़ा : सीरवी समाज अटबड़ा की ओर से अटबड़ा में समाज के भूखंड पर तीन दिवसीय समाज भवन व मुख्य द्वार के निर्माण के उपलक्ष में तीन दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में धर्मगुरु दीवान साहब व आईमाता बेल का भव्य बधावा किया गया। इससे पूर्व संस्था में भजन गायक गजेन्द्र अजमेरा व हेमराज गौयल, महेंद्र सीरवी ने आईमाता एवं अन्य देवी-देवताओं के भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजनों के कार्यक्रम में चढ़ावों की बोलियों में समाज बंधुओं ने बह-चढ़कर हिस्सा लिया। धर्मगुरु दीवान साहब के स्वागत के लिए वरघोड़ा निकाला गया। नवयुक्त मंडल के सदस्य धर्म ध्वज के साथ आईमाता के जयकारे लगाते चल रहे थे। शोभायात्रा जहां जहां गुजरी लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सीर पर कलश धारण कर मंगल गान करते महिलाएं चल रही थीं। वरघोड़े रथ में सवार धर्मगुरु दीवान माधवसिंह सभी का अभिवादन कर रहे थे। वरघोड़े में अनेक गैर मंडलों ने भाग लिया। रंग बिरंगी छतरियां एवं कलर पेपर से सुसज्जित डांडिया के साथ गैर नृत्य कर रहे सदस्य सभी के आकर्षक का केन्द्र रहे। वरघोड़ा विभिन्न मार्गों से होता हुआ समाज भूखंड परिसर में पहुंचकर धर्मसभा में परिवर्तित हो गया। धर्मगुरु दीवान साहब ने कहा



की धर्म की नींव मजबूत होनी चाहिए। व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म ही हमारी पहचान है। धर्म गुरु दीवान साहब ने चढ़ावों के लाभार्थियों का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पथारे सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक पुखराज सीरवी ने कहा की सीरवी समाज के लिए गर्व की बात है की अपनी समाज बहुत ही मेहनती कोम है। सीरवी समाज ने व्यापार और सरकारी नौकरी में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने समाज के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समाज बंधुओं ने आईमाता धर्मरथ बेल का भव्य बधावा किया। श्रद्धालुओं ने आईमाता के बेल रथ के दर्शन किए। धर्मसभा में कर्नाटक और

अन्य प्रांतों से आए सभी सीरवी समाज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने समाज विकास पर चिंतन कर सुदृढ़ समाज का निर्माण करने की बात कही। वक्ताओं ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को समाज के बुजुर्गों को साथ लेकर समाज विकास में आगे बढ़े। इस मौके पर सोजत विधानसभा क्षेत्र की विधान शोभा चौहान ने कहा की संप्रति समाज के निर्माण के लिए सभी को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर कोटवाल मोहनलाल पंवार, जिमेदारी जिवाराम काग, अध्यक्ष मोहनलाल आगलेचा, बाबूलाल आगलेचा, जगदीश चोयल, मोहनलाल बर्ना, रामलाल गेहलोत, भगवान राम चोयल सहित समाज के अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।

करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या

टाटा में एन एच जाम-आगजनी, 48 घंटे का अल्टिमेटम अन्यथा झारखंड बंद

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

जमशेदपुर, जमशेदपुर के बालीगुमा में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका शव एनएच-33 पर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल मोड़ से करीब 500 मीटर अंदर खेत में पड़ा हुआ मिला। उनके सिर में गोली मारी गई थी। मौके से विनय की स्कूटी और पिस्तौल बरामद की गई है।

इससे गुस्साए करणी सेना के सदस्यों ने आगजनी के बाद एनएच जाम कर दिया। तीन घंटे बाद सिटी एस्पपी के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी माने। इसके बाद देर रात 1 बजे एनएच-33 से जाम खत्म हुआ। डिमना रोड आस्था स्पेश टाउन निवासी विनय सिंह की हत्या घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में करणी सेना के समर्थक घटनास्थल पर पहुंच गए।



सरायकेला खरसावां जिले के समर्थक भी वहां पहुंचे लगे। वहां मौजूद पुलिस टीम से उनकी बहस हुई और लोगों ने पुलिस को धक्का देकर घटनास्थल से खदेड़ दिया। स्थिति को बिगड़ते देख पटमदा डीएसपी बचनदेव कुंजर, उलीडीह थाना प्रभारी कुमार अभिषेक, मानगो थाना प्रभारी

निरंजन कुमार और सिदोगोड़ा थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी मौके पर पहुंचे और किसी तरह भीड़ को शांत कराया। इस दौरान करीब तीन घंटे तक शव वहीं पड़ा रहा और हंगामा होता रहा। आक्रोशित भीड़ पुलिस को शव नहीं उठाने दे रही थी। बाद में पुलिस ने लोगों को शांत करवाकर शव को

एमजीएम अस्पताल भेजा। शव को मोचरी में रखा गया है। विनय सिंह की हत्या के बाद घटनास्थल से लेकर डिमना चौक तक बवाल होता रहा। रात 10 बजे से लेकर एक बजे तक समर्थकों ने आंदोलन किया और एनएच-33 को पूरी तरह जाम कर दिया। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई।

इधर, घटना से नाराज समर्थकों ने डिमना चौक के पास एनएच-33 को जाम कर दिया। इससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात ठप हो गया। मौके पर भाजपा और आजसू पार्टी के कई नेता भी पहुंचे और हत्या की निंदा करते हुए जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। विनय सिंह उलीडीह थाना क्षेत्र के आस्था स्पेश टाउन में रहते थे। डिमना चौक पर ही उनका टाइल्स की दुकान है। परिजनों के मुताबिक, वे रविवार सुबह 11 बजे घर से निकले थे। आमतौर पर वे

दोपहर 4 बजे तक खाना खाने घर लौटते थे, लेकिन न तो दुकान पहुंचे और न ही घर आए। जब काफी देर तक उनका पता नहीं चला और फोन भी बंद आया तो परिजन रात 8 बजे उलीडीह थाना पहुंचे और पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर खोजबीन शुरू की और रात 8 बजे उनका शव बरामद किया। पुलिस का कहना है कि शव पर चोटियां लग चुकी थीं, जिससे यह साफ है कि हत्या दोपहर 12 बजे के आसपास उनकी हत्या की गई होगी। पुलिस को विनय के बाएं हाथ में एक पिस्तौल मिली है, जिससे शुरुआती जांच में यह बात सामने आ रही है कि या तो हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश हुई है, या फिर यह पूरी तरह सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल व अन्य सबूतों के आधार पर जांच कर रही है।

22 अप्रैल - विश्व पृथ्वी दिवस पर विशेष पृथ्वी हमारे अस्तित्व का आधार...!

राजा पृथु ने धरती का किया दोहन, हुई ये धरा समतल उपजाऊ मोहन। भारत में पृथ्वी को माता कहा जाता, राजा का पूरी पृथ्वी से ही रहा नाता। सबसे पहले धरती पे उगाया अनाज, संपूर्ण विश्व पे पृथु ने ही किया राज।

राजा पृथु ने धरती का किया दोहन, हुई ये धरा समतल उपजाऊ मोहन। सुबह नींद से जाग करों चरण स्पश, जीवन सुखदायी हो धरा पे हो हर्ष। माता भूमि: पुत्रोऽहम पृथिव्या: मंत्र, धरती पे पैर रख उच्चारण करों यत्।

राजा पृथु ने धरती का किया दोहन, हुई ये धरा समतल उपजाऊ मोहन। संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक, कृषि से लेकर भवन के निर्माण तक। 'पृथ्वी' आराधना शुभ कार्यों में होती,



अन्न, जल, औषधि, फलफूल, वस्त्र देती।

राजा पृथु ने धरती का किया दोहन, हुई ये धरा समतल उपजाऊ मोहन। हम धरती के ऋण से कभी न मुक्त, सबकुछ असीम दें कर देती है तुम। पृथ्वी हमारे अस्तित्व का आधार है, दिया हमें जो आश्रय ये उपकार है।

संजय एम तराणेकर